



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042020-219081
CG-DL-E-20042020-219081

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 20, 2020/चैत्र 31, 1942

No. 103]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 20, 2020/CHAITRA 31, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2020

प्रकरण संख्या: एडीडी-ओ आई-06/2020

विषय: चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कॉपर और कॉपर एलाय फ्लैट रोल्ड उत्पाद" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/7/2020-डीजीटीआर.— 1. मै. अग्रवाल मेटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे 'आवेदक' भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड (जिन्हें यहां आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से 'कॉपर और कॉपर एलाय फ्लैट रोल्ड उत्पाद'

(जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” या ‘विचाराधीन उत्पाद’ या ‘पीयूसी’ भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच का अनुरोध किया गया है।

- आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति हुई है तथा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

- विचाराधीन उत्पाद कॉपर के फ्लैट रोल्ड उत्पाद हैं जैसे कॉपर शीट, कॉपर प्लेट, कॉपर स्ट्रिप, कॉपर फॉइल और कॉपर तथा उसके एलाय के अन्य परतदार रूप। यह शीट के रूप में अथवा फॉइल के रूप में हो सकते हैं। विचाराधीन उत्पाद में परिष्कृत कॉपर या जिंग और टिन के साथ कॉपर एलाय अर्थात् कॉपर ज़िंक बेस एलाय (पीतल) और कॉपर टिन बेस एलाय (फॉस्पर ब्रॉन्ज) शामिल हैं। सभी अन्य कॉपर एलाय पीयूसी के दायरे से बाहर हैं।
- कॉपर फ्लैट रोल्ड उत्पादों का प्रयोग विद्युत वितरण, इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रॉनिक स्विच गियर और यंत्रों, ऑटोमोबाइल टर्मिनल कनेक्टर और ऑटोमोटिव इलैक्ट्रॉनिक, सेनेटरी फिटिंग, रेडिएटर और हीट एक्सचेंजर तथा चाबी और तालों, बटन और जिपर आदि में किया जाता है।
- संबद्ध उत्पादों को अधिनियम के अध्याय शीर्ष 74 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। यद्यपि, उत्पाद का विहित वर्गीकरण 74091100, 74091900, 74092100, 74092900, 74093100, 74093900, 74094000, 74099000, हैं तथापि, विचाराधीन उत्पाद का आयात 74101100, 74101200 के अंतर्गत भी किया गया है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

- आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही सबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। पाटित आयातों और आवेदक द्वारा विनिर्मित घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु के बीच तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्य या अंतिम प्रयोग की दृष्टि से कोई ज्ञात अंतर नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये दोनों प्रथम दृष्टया तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए।

उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन)

- आवेदक ने भिन्न-भिन्न उत्पाद किस्मों की उत्पादन लागत में अंतर पर विचार करते हुए जांच के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव किया है।

1	स्थिति	पीतल = 1 तांबस = 2 फॉस्पर ब्रॉन्ज = 3
2	रूप	फॉइल = 1 शीट/प्लेट = 2 स्ट्रिप = 3
3	ग्रेड	CuZn30-33, CuZn35-37, CuZn10, CuZn40, CuZn5, CuZn15, CuZn20, ताबा, CuSn4, CuSn5, CuSn6, CuSn8

उदाहरण के लिए CuZn30-33 की पीतल की फॉइल को 11CuZn30-33 के रूप में वर्णित किया जा सकता है और CuSn8 की ताबे की स्ट्रिप को 23CuSn8 के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

8. हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना के पैरा 26 में उल्लिखित समयावधि के अनुसार प्रस्तावित पीसीएन प्रणाली की उपयुक्तता या अन्यथा के संबंध में अपने अनुरोध कर सकते हैं।

घरेलू उद्योग

9. यह आवेदन अग्रवाल मैटल वर्क्स प्रा. लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है जो समान वस्तु के प्रमुख घरेलू उत्पादकों में से एक हैं। आवेदन को संगठित क्षेत्र में सभी ज्ञात घरेलू निर्माता द्वारा समर्थित किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि उसमें न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित हैं।
10. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आवेदक भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख अनुपात है यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से अथवा उसके द्वारा इस नियमावली के नियम 2 (ख) नियम 5(3) में निहित प्रावधानों के संबंध में किया गया है।

कथित पाटन का आधार

चीन के लिए सामान्य मूल्य

11. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1, नियम 7 के अनुसार किया जाना चाहिए। आवेदक ने चीन के एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है और यह बताया है कि उसमें दिए गए प्रावधानों के अनुसार चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने का निदेश दिया जाए कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं। आवेदक ने दावा किया है कि चीन की घरेलू लागत और कीमतों को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक चीन के निर्यातक बाजार अर्थव्यवस्था के परीक्षण को पास न कर लें। आवेदकों ने यह बताया है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। उपर्युक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता के मद्देनजर और चीन से प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार अनुमानित किया गया है।
12. आवेदक ने सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी उचित तीसरे देश का सुझाव नहीं दिया है और इस प्रकार सामान्य मूल्य के निर्धारण का विकल्प का पता नहीं लगाया गया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य को भारत में देय कीमत के आधार पर निर्धारित किया गया है।
13. संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री कॉपर है। कॉपर की कीमत लंदन मेटल एक्सचेंज (एल एम ई) द्वारा अनुरक्षित होती है। अतः चीन में सामान्य मूल्य का निर्धारण पीओआई के दौरान कॉपर की एल एम ई कीमतों के आधार पर किया गया है जिसमें प्रसंसकरण लागत, एस जी ए लागत, वित्तीय लागत और अन्य आय (आयों) के लिए समायोजन किए गए हैं।

कोरिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने दावा किया है कि कोरिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड में विचाराधीन उत्पाद की कीमत के संबंध में कोई सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। उसमें सामान्य मूल्य के परिकलन के लिए ऐसे किसी देश को कोरिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत लेने के लिए किसी समुचित तीसरे देश का सुझाव भी नहीं दिया है। संबद्ध वस्तु के उत्पादन के लिए प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री कॉपर है और कॉपर की कीमत लंदन मेटल एक्सचेंज (एल एम ई) द्वारा अनुरक्षित की जाती है। अतः सामान्य मूल्य का परिकलन तदनुसार, जांच अवधि के दौरान एल एम ई कीमतों के आधार पर प्रसंसकरण लागत, एस जी ए लागत, वित्तीय लागत और अन्य आय (आयों) के लिए समायोजनों के साथ परिकलित किया गया है। घरेलू उत्पादकों के लिए खपत मानक अपनाए गए हैं।

निर्यात कीमत

15. निर्यात कीमत संबद्ध देशों में से प्रत्येक के लिए डी जी सी आई एंड एस के सौदावार आंकड़ों के आधार पर निर्धारित की गई है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय माल-भाड़ा व्यय, पत्तन व्यय, बैंक प्रभारों और वैट (केवल चीन के लिए) के लिए कीमत संबंधी समायोजन किए गए हैं। निर्यात कीमत कारखाना द्वार स्तर पर निर्धारित की गई है।

पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से पी यू सी के संबंध में निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक पाटन मार्जिन दर्शाती है। इस बात के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से पी यू सी को संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संपर्क

17. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है। आवेदक ने पाटित आयातों की मात्रा में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन तथा खपत की दृष्टि से भी वृद्धि होने, कीमत कटौती, लाभप्रदता, नकद लाभों और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में विकृति की दृष्टि से कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

पाटनरोधी जांच की शुरूआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा और उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, एतद्वारा जांच की शुरूआत करते हैं।

संबद्ध देश

19. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण., कोरिया गणराज्य, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड हैं।

जांच की अवधि (पी ओ आई)

20. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (जिसे आगे पीओआई भी कहा गया है) 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 (12 महीने) की है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2016- 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल, 2017- 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018- 31 मार्च, 2019 और पी ओ आई की अवधियां शामिल होंगी।

प्रक्रिया

21. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच के लिए पालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

22. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से लिखा जा रहा है।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
24. सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जा सकते हैं :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
व्यापार उपचार महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना भी अपेक्षित है।

समय-सीमा

26. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न इस विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित रूप में प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए और वह इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर ऊपर उल्लिखित पते पर प्राधिकारी को पहुंच जानी चाहिए। यदि विहित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी की गई व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में सस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
29. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा :-

(i) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और

(ii) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।

30. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां चार (4) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।
31. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
32. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय

सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
35. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

36. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2020

Case No. ADD-OI- 06/2020

Subject: Initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of “Copper & Copper Alloy Flat Rolled Products” originating in and exported from China PR, Korea RP, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, and Thailand.

F. No. 6/7/2020-DGTR.—M/s. Agrawal Metal Works Private Limited (hereinafter also referred to as the “Applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for Anti-dumping investigation on imports of “Copper and Copper Alloy Flat Products” (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”) from China PR, Korea RP, Malaysia, Nepal Sri Lanka and Thailand (hereinafter also referred to as “subject countries”).

2. The Applicant has alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry, and has requested for imposition of the anti-dumping duties on the import of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Product under Consideration

3. The product under consideration is flat rolled products of copper, such as copper sheets, copper plates, copper strips, copper foils and other flattened forms of copper or its alloys. It may be in sheet form or coil form. The product under consideration includes refined copper or copper alloys with Zinc and tin i.e., Copper-Zinc base alloys (Brass) and Copper-Tin base alloys (Phosphor Bronze). All other copper alloys are beyond the scope of PUC.
4. Copper flat rolled products are used in power distribution, electrical & electronic switchgears & devices, Automobile Terminal Connector and Automotive Electronics, Sanitary Fittings, Radiators and Heat Exchangers and Key and Locks, Buttons, Zippers etc.
5. The subject products are classified under Chapter Heading 74 of the Act. While the prescribed classification of the product is 74091100, 74091900, 74092100, 74092900, 74093100, 74093900, 74094000, 74099000, the product under consideration has also been imported under 74101100, 74101200. The customs classifications are indicative only and are not binding on the scope of the present investigations.

Like Article

6. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There is no known difference either in the technical specification, quality, functions or end-user of the dumped imports and the domestically produced subject goods manufactured by the Applicant. The Authority notes that the two are prima facie technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules.

Product Control Number (PCN)

7. The Applicant has proposed following PCN methodology for the purpose of the investigation, considering difference in the cost of production of the different product types.

1	Condition	Brass = 1 Copper = 2 Phosphor Bronze = 3
2	Form	Foil = 1 Sheet/Plate = 2 Strip = 3
3	Grade	CuZn30-33, CuZn35-37, CuZn10, CuZn40, CuZn5, CuZn15, CuZn20, Copper, CuSn4, CuSn5, CuSn6, CuSn8

For instance, brass foil of CuZn30-33 can be described as 11CuZn30-33 and copper strip of CuSn8 can be described as 23CuSn8.

8. The interested parties may make their submissions with regard to appropriateness or otherwise of the proposed PCN system as per the timeline mentioned in Para 26 of this notification.

Domestic Industry

9. The Application has been filed by Agrawal Metal Works Private Limited, one of the major domestic producers of the like articles. The Application has been supported by all known domestic producers in the organized sector. The Applicant has claimed that it has neither imported the subject goods from the subject countries nor is related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or any importer of PUC in India.
10. In view of information on record, the Authority notes that the Applicant accounts for a major proportion of the Indian production and the application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

Basis of alleged dumping**Normal Value for China**

11. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy, and the normal value should be determined in terms of Annexure I, Rule 7 of the Rules. The Applicant has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and has stated that in terms of provisions contained therein the Chinese producers should be directed to show that market economy conditions prevail in the industry

producing the subject goods. The Applicant has claimed that Chinese domestic costs and prices cannot be accepted unless the Chinese exporters pass the tests of market economy. The Applicants have stated that for China, normal value should be determined in accordance with para-7 and 8 of Annexure I of the Rules. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from China, normal value of the Subject Goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure I of the Rules.

12. The Applicant has not suggested any appropriate market economy third country for determining normal value and hence that option for determination of normal value has not been explored. Accordingly, the normal value has been determined on the basis of price payable in India.
13. The major raw material consumed for the production of the subject goods is Copper. The price of copper as maintained by London Metal Exchange (LME). Therefore, Normal Value in China has been determined on the basis of the LME prices of Copper during the POI, with adjustments that have been made on account of the processing cost, SGA cost, financial cost and other income(s).

Normal Value for Korea, Malaysia, Nepal, Sri Lanka and Thailand

14. The Applicant has claimed that there is no publicly available information on the price of the PUC in Korea, Malaysia, Nepal, Sri Lanka and Thailand. It has also not suggested any appropriate third country for taking export price of subject goods from Korea, Malaysia, Nepal, Sri Lanka and Thailand to such a country, for construction of normal value. The major raw material consumed is copper for the production of the subject goods, and the price of copper is maintained by London Metal Exchange (LME). Therefore, the normal value has accordingly been constructed on the basis of the LME prices of Copper during the POI, with adjustments made on account of the processing cost, SGA cost, financial cost and other income(s). The consumption norms of the domestic producers have been adopted.

Export Price

15. The export price has been determined for each of the subject countries based on DGCI&S transaction-wise data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses, bank charges, and VAT (only for China). The export price has been determined at ex-factory levels.

Dumping Margin

16. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin above the *de-minimis* in respect of the PUC from the subject countries. There is prima facie evidence that the PUC from subject countries is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

Injury and Causal Link

17. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and also in relation to production and consumption in India, price undercutting and deterioration in performance of the domestic industry in respect of profitability, cash profits and return on capital employed. There is prima facie evidence that the dumped imports from subject countries are causing injury to the domestic industry.

Initiation of Anti-dumping Investigation

18. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Subject Countries

19. The subject countries for the present investigation are China PR, Korea RP, Malaysia, Nepal, Sri Lanka and Thailand.

Period of Investigation (POI)

20. The period of Investigation (hereinafter also referred to as “POI”) is from 1st January 2019 to 31st December 2019 (12 months). The injury investigation period will cover the periods 1st April 2016-31st March 2017, 1st April 2017- 31st March 2018, 1st April 2018- 31st March 2019 and the POI.

Procedure

21. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of information

22. The known exporters in the subject countries, their government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods, and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
24. The information/ submission may be submitted to:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street
New Delhi -110001

25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time-Limit

26. In view of the special circumstances arising from COVID-19 pandemic, any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within sixty days from the date of issue of this notification. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.
27. All interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time-limit.

Submission of Information on Confidential basis

28. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
29. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:
- i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
 - ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).
30. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each.
31. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

32. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

36. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-Corporation

37. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority